



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

खण्ड 38] शिमला, शनिवार, 31 मार्च, 1990/10 चैत्र, 1912 [संख्या 13

विषय सूची		
भाग 1	वैधानिक नियमों को छोड़ कर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि ..	282—284 तथा 300
भाग 2	वैधानिक नियमों को छोड़ कर विभिन्न विभागों के अध्यक्षों और जिला मैजिस्ट्रेटों द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि ..	284
भाग 3	अधिनियम, विधेयक और विधेयकों पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन, वैधानिक नियम तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, फाइनैन्शियल कमिश्नर तथा कमिश्नर ग्राफ इन्कम टैक्स द्वारा अधिसूचित आदेश इत्यादि ..	285—294
भाग 4	स्थानीय स्वायत्त शासन: म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नोटिफाइड और टाउन एरिया तथा पंचायती राज विभाग ..	—
भाग 5	वैयक्तिक अधिसूचनाएं और विज्ञापन ..	294—300
भाग 6	भारतीय राजपत्र इत्यादि में से पुनः प्रकाशन ..	—
भाग 7	भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की वैधानिक अधिसूचनाएं तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी अधिसूचनाएं ..	—
—	अनुपूरक ..	—

31 मार्च, 1990/10 चैत्र, 1912 को समाप्त होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित विज्ञप्तियां 'असाधारण राजपत्र, हिमाचल प्रदेश' में प्रकाशित हुईं:—

विज्ञप्ति की संख्या	विभाग का नाम	विषय
संख्या 1-18/90-वि० स०, दिनांक 21 मार्च, 1990. संख्या एफ० एस० (चम्बा) 1201-51 दिनांक 14 मार्च, 1990. संख्या एल० एस० जी०-वी० (15) 4/7 5-II, दिनांक 16 मार्च, 1990.	विधान सभा सचिवालय कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा स्थानीय स्वशासन विभाग	अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा वर्ष 1990 के लिये सभापति तालिका सदस्य (पैनल ग्राफ प्रिजाइडिंग मेंबरज) का मनोनयन पिछले सभी आदेशों का अधिकरण करते हुए जिला दण्डाधिकारी, चम्बा द्वारा अधिकतम परचून दरों के निर्धारण का प्रकाशन। राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश द्वारा नगरपालिका सदस्यों की पदावधि समाप्त होने पर नगरपालिका के लम्बित निर्वाचन तक कुछ प्रशासक एवं अधिकारियों की नियुक्ति करना, इसके अंग्रेजी रूपान्तर सहित प्रकाशन।
संख्या एफ० डी० एस० ए०(3) -1/86-II, दिनांक 19 मार्च, 1990.	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग Directorate of State Lotteries	हिमाचल प्रदेश बाट और माप मानक (प्रवर्तन) (संशोधन) नियम, 1990 का इसके अंग्रेजी रूपान्तर सहित प्रकाशन। Results of 21st draw of Shimla Super Weekly (21-3-1990), 21st draw of Maa Durga Super Weekly (22-3-1990), 81st draw of Himachal Weekly (22-3-1990) and 99th draw of Golden Weekly (23-3-1990).
संख्या 1-26/90-वि० स०, दिनांक 28 मार्च, 1990. No. 8-155/73-DP (Apptt.)(ii), dated 13th March, 1990.	विधान सभा सचिवालय Personnel (Apptt. II) Department	हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 1990 (1990 का विधेयक संख्यांक 1) का इसके अंग्रेजी रूपान्तर सहित प्रकाशन। Sh. K. C. Mahajan is ceased to be a member of HPSEB—Publication thereof.

भाग 1—वैधानिक नियमों को छोड़ कर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि

सिचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 17 मार्च, 1990

संख्या सिचाई 11-109/88-मण्डो.—यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यवस्था पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव चवाड़ी, तहसील सदर, जिला मण्डो, (हिमाचल प्रदेश) में बहू बैली सिचाई परियोजना जोन-1 के निर्माण हेतु भूमि अर्जन करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना में जैसा कि निम्न विवरणों में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इस से सम्बन्धित हों या हो सकते हैं को जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी ऐसा हितवद्ध व्यक्ति, जिसे उक्त परियोजना में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, ता वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाह्वी, व्यास सतलुज लिंक परियोजना, मण्डो के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विस्तृत विवरणों

जिला: मण्डो		तहसील: सदर		
गांव	खसरा नम्बरा	क्षेत्र		
		बी०	गि०	निस्वां
1	2	3	4	5
चवाड़ी/288	253/2	2	15	12
	253/1/1	1	5	4
	254/2/1	1	1	0
	268/3/1	0	10	8
	260/1	0	0	12
	268/1/1	0	1	0
	328/3	1	8	11
	328/1	1	3	13
	327	0	19	4
	324/1	0	18	5
	330/3	1	3	6
	332/2/1	0	10	5
कुल	12	11	17	16

आदेश द्वारा,
श्री 0 कु० महापात्र,
सचिव।

LABOUR DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 17th March, 1990

No. 19-8/89-Shram.—Whereas it appears to the Governor, Himachal Pradesh, that there is an industrial dispute between Miss Elahwanti Devi and the Resident Engineer, Shanan Power House, Punjab State Electricity Board, Jogindernagar, District Mandi, Himachal Pradesh;

And whereas after considering the report submitted by the Conciliation Officer under section 12 (4) of the Industrial Disputes Act, 1947, the Governor, Himachal Pradesh is satisfied that the matter may be referred to the Labour Court Himachal Pradesh.

Now, therefore, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in him under section 12(5) of the Industrial Disputes Act, 1947 (Act No. 14 of 1947) hereby refer this case to the Labour Court, Himachal Pradesh constituted under section 7 of the Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication as under:—

“Whether the termination of services of Miss Elahwanti Devi by the Resident Engineer, Shanan Power House, Punjab State Electricity Board, Jogindernagar, District Mandi is legal and maintainable? If illegal, to what relief and service benefits Miss Elahwanti Devi is entitled?”

By order,

Sd/-

F. C.-cum-Secretary (Labour).

LAW DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Shimla-2, the 14th March, 1990

No. LLR-E(9)4/89-Legislation.—Read “20-10-89” for the word “Do” occurring in column (3) against serial No. 4 and 5 of the table of this Department Notification o even dated 23-12-1989.

Sd/-

Secretary.

बहुदेशीय परियोजना एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 21 फरवरी, 1989

संख्या विद्युत-छ (5)-38/88.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय जल विद्युत परियोजना निगम सीमित (एन० एच० सी० सी०) जोकि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी० सी०) क अर्थात्तर्गत सरकार क स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यवसाय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामतः ग्राम चेहली, ह० व० नं० 13, तहसील व जिला चम्बा में चमेरा जल विद्युत परियोजना के जलाशय क्षेत्र के विलयन हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है। अतएव एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणों में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु यह घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाह्वी, चमेरा जल विद्युत परियोजना, चम्बा को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि का रेखांक भू-अर्जन अधिकारी, चमेरा जल विद्युत परियोजना हिलफुटस डाकघर मुल्तानपुर, जिला चम्बा के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विवरणी

जिला: चम्बा		तहसील: चम्बा	
गांव	खसरा न०	क्षेत्र	
		बी०	निस्वां
1	2	3	4
चेहली	27	1	16
ह० व० नं० 13	28	0	7

1	2	3	4
	29	2	18
	31	0	11
	32	0	14
	33	1	15
	34	1	7
	36	0	7
	37	0	3
	38	0	3
	39	0	19
	40	0	8
	41	0	4
	42	0	8
	43	0	8
	44	0	2
	45	2	5
	46	1	2
	47 मिन्	4	0
	47 मिन्	1	16
	48	1	1
	49	1	3
	50	0	3
	51	3	3
	52	1	16
	53	0	12
	55	0	18
	56	0	14
	60	0	12
	61	0	6
	62	0	19
	63	0	6
	64	0	7
	65	1	7
	66	3	2
	460	1	2
किता ..	36	39	4

आदेश द्वारा,
कैलाश चन्द महाजन,
सचिव ।

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 16 सितम्बर, 1989

संख्या लो0 नि0 (ख) 7(1) 126/89.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव कराल, तहसील कोटखाई, जिला शिमला में कलदोग-कुईतल सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जन करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना, ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

4. कोई भी हितवद्ध व्यक्ति, जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने

के तीस दिन (30) की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता (1), लोक निर्माण विभाग, शिमला-2 के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।

विवरणी

जिला: शिमला

तहसील: कोटखाई

गांव	खसरा नं0	क्षेत्र	
		बीघा	बिस्वा
1	2	3	4
कराल	111	1	16
	116	2	4
	118	9	4
	159	5	14
	137	0	16
	133	0	18
	134	1	2
	136	1	5
	17	8	0
	142	1	8
	135	0	8
	196/165	7	11
किता ..	12	40	6

शिमला-171002, 14 मार्च, 1990

संख्या लो0 नि0 (ख) 7(1) 84/88.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव नकराड़ी, तहसील जुब्बल, जिला शिमला में पटसारी-अड्डा सड़क के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता (1), लोक निर्माण विभाग, शिमला-2 को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश देने का एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है ।

3. भूमि का रेखांक भू-अर्जन समाहर्ता (1), लोक निर्माण विभाग, शिमला-2 के कार्यालय में भूमि का निरीक्षण किया जा सकता है ।

विवरणी

जिला: शिमला

तहसील: जुब्बल

गांव	खसरा नं0	क्षेत्र	
		बी0	बि0
1	2	3	4
नकराड़ी	986/555/1	0	10
	1089/555/1	0	13
किता ..	2	1	3

शिमला-2, 14 मार्च, 1990

संख्या लो0 नि0 (ख) 7(1) 97/88.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ नामतः गांव पराली, तहसील कोटखाई, जिला शिमला में तृतीय श्रेणी के लिए खनेडी में विश्राम गृह के निर्माण हेतु भूमि ली जानी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

2. यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों की सूचना हेतु की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, शिमला-2, हिमाचल प्रदेश को उक्त भूमि का अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्वारा निर्देश दिया जाता है।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, यह निर्देश देते हैं कि अत्यावश्यक मामला होने के कारण भू-अर्जन समाहर्ता (1), लोक निर्माण विभाग, शिमला-2 को उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन सूचना के प्रकाशन से 15 दिन की अवधि के समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकता है।

4. भूमि का रेखांक भू-अर्जन समाहर्ता (1), लोक निर्माण विभाग, शिमला-2, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निरीक्षण किया

जा सकता है।

विस्तृत विवरणों

जिला : शिमला

तहसील : कोटबाई

गांव 1	खसरा नं० 2	सेर	
		बी० 3	बि० 4
पराली	1185/1	1	8
कित्ता	1	1	8

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
आयुक्त एवं सचिव।

भाग 2—बंधनान्तरित नियमों को छोड़ कर विभिन्न विभागों के अध्यक्षों और जिला मैजिस्ट्रेटों द्वारा अधिसूचनाएं इत्यादि

FOOD AND SUPPLIES DEPARTMENT

OFFICE ORDER

Shimla-2, the 19th March, 1990

No. 9-154/73-CS-III-6690.—Whereas Shri Siri Dhar Sharma, Sub-Inspector, Food and Supplies, presently posted at Nankhari in Shimla district has been convicted on the charge of criminal breach of trust under section 409 Indian Penal Code by the Sub-Divisional Judicial Magistrate, Rampur Bushehar, District Shimla, and the conviction has also been upheld by the Additional Sessions Judge, Shimla in appeal filed by the said Shri Siri Dhar Sharma, against the judgement of the trial Court.

And whereas the said Shri Siri Dhar Sharma, was given an opportunity to Show Cause as to why he may not be dismissed from service on the ground of his conduct which has led to his conviction.

And whereas the reply of the Show Cause Notice received from the said Shri Siri Dhar Sharma, has been considered and found unsatisfactory as he has failed to show any extenuating circumstances in relation to the conduct which led to his conviction.

And whereas I am of the considered view that the conduct of the said Shri Siri Dhar Sharma is such as to render his further retention in the public service undesirable.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Rule 19(1) of the Central Civil Services (CCA) Rules, 1965, I hereby order the dismissal from service of the said Shri Siri Dhar Sharma, with immediate effect in public interest.

S. N. VERMA,
Director.

Office of the Assistant Registrar Co-operative Societies
Mandi District, Himachal Pradesh

OFFICE ORDERS

Mandi, the 6th March, 1990

No. Co-op. M.—Whereas the Sericulture Co-operative Industrial Society Limited Mandi, District Mandi Himachal Pradesh was put under Liquidation vide this Office order No. 4-290 59-920/4-8 dated 31-8-1971.

Whereas the Inspector Co-operative Societies Sadar vide his memo No. 108 dated 15-2-1990 has reported that the members of the said society are now interested to revive the said society. The circle Inspector has also recommended the case for the revival of the Society, as the working of the Society has been improved.

Now, therefore, I, B. D. Grover Assistant Registrar, Co-operative Societies Mandi, District Mandi Himachal Pradesh in exercise of the powers under section 83 (1) of Himachal Pradesh Co-operative Societies Act, 1968 (Act No. 3 of 1969), do hereby cancel the order of winding up issued vide order referred above and revive the said society with immediate effect, subject to the condition, the society will function smoothly and will show good progress within 6 months period.

Mandi the 6th March, 1990

No. Coop. M.—Whereas the Ravi Dass Leather Industrial Co-operative Society Limited Bhojpur, Tehsil Sundernagar was put under liquidation vide this Office order No. Co-op. M. 291/59-3241-43 dated 28-3-1972.

Whereas the Inspector Co-operative Societies, Sundernagar vide his memo No. 140 dated 21-2-1990 has reported that the members of the said Society are now interested to revive the said Society. The circle Inspector has also recommended the case for the revival of the society as the working of the society has been improved.

Now, therefore, I, B. D. Grover, Assistant Registrar Co-operative Societies Mandi, District Mandi Himachal Pradesh in exercise of the powers under section 83 (1) of Himachal Pradesh Co-operative Societies Act, 1968, (Act No. 3 of 1969), do hereby cancel the order of winding up issued vide order referred above and revive the said society with immediate effect, subject to the condition, that the society will function smoothly and will show good progress within 6 months period.

B. D. GROVER,
Assistant Registrar,
Co-operative Societies Mandi.

Office of the Assistant Registrar Co-operative Societies
Sirmaur, District Nahan

ORDER

Nahan, the 20th March, 1990

No. Coop. 3 (44)/75.—Whereas the liquidator of the Kolar Tubewell Irrigation Co-operative Society Limited Kolar, Post Office Kolar, Tehsil Paonta, District Sirmaur Himachal Pradesh has submitted his final report of the liquidation and after considering the report of the liquidator, I, H. S. Tomar, Assistant Registrar, Co-operative Societies Sirmaur, District Nahan in exercise of the powers conferred upon me under section 83 (2) of the Himachal Pradesh Co-operative Societies Act, 1968 (Act No. 3 of 1969) do hereby order the cancellation of the registration of the Kolar Tubewell, Irrigation Co-operative Society Limited Kolar, Post Office Kolar, Tehsil Paonta, District Sirmaur.

H. S. TOMAR,
Assistant Registrar,
Co-operative Society Nahan.

भाग 3—अधिनियम, विधेयक और विधेयकों पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन, वैधानिक नियम तथा हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, फाइनेशियल कमिशनर तथा कमिशनर आफ इन्कम टैक्स द्वारा अधिसूचित आदेश इत्यादि

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 15 फरवरी, 1989

सं० गृह-II(बी०) 2-3/81.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा और अग्निशमन सेवा विभाग में इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध “अ” के अनुसार कम्पनी कमाण्डर/वरिष्ठ प्रशिक्षक/भण्डार अधिकारी के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा और अग्निशमन सेवा विभाग में कम्पनी कमाण्डर/वरिष्ठ प्रशिक्षक/भण्डार अधिकारी के भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1988 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम.—कम्पनी कमाण्डर/वरिष्ठ प्रशिक्षक/भण्डार अधिकारी की पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतनमान, अर्हताएं भर्ती की पद्धति उपाबन्ध “अ” में विनिर्दिष्ट है।

3. निरसन और व्यावृत्तियाँ.—इस विभाग की अधिसूचना संख्या 17-4/66-गृह, तारीख 20-1-1971 द्वारा अधिसूचित कम्पनी कमाण्डर/वरिष्ठ प्रशिक्षक/भण्डार अधिकारी के पदों के भर्ती और प्रोन्नति नियम एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं।

परन्तु ऐसे निरसन के उक्त नियमों के पूर्व प्रवर्तन या उनके अधीन की गई किसी नियुक्ति या कार्रवाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उपाबन्ध “अ”

गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश में कम्पनी कमाण्डर/वरिष्ठ प्रशिक्षक/भण्डार अधिकारी के पद के लिए भर्ती एवम् प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम कम्पनी कमाण्डर/वरिष्ठ प्रशिक्षक/भण्डार अधिकारी।
2. पदों की संख्या कम्पनी कमाण्डर=15, वरिष्ठ प्रशिक्षक=1, भण्डार अधिकारी=1, कुल पद=17.
3. वर्गीकरण वर्ग-3 (अलिपिकीय)
4. वेतनमान रु० 800-25-850/30-1000/40-1200/50-1400.
5. न्यून पद अथवा अधून पद अधून।
6. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु 18 से 50 वर्ष:

परन्तु सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा तदर्थ या सविदा पर नियुक्ति सहित, पहले ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगी।

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ आधार पर नियुक्ति किया गया अभ्यर्थी स रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक हो गया हो, तो वह तदर्थ या सविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में उतना ही

शिथिलीकरण किया जा सकेगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है:

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में शामिलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारियों को नहीं दी जाएगी जो बाद में ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से शामिल किए गए हैं/किए गए थे।

टिप्पणी-1.—सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना यथास्थिति, उस वर्ष के प्रथम दिन से की जाएगी जिसमें आवेदन आमंत्रित करने के लिए पद विज्ञापित या नियोजन-नालयों को अधिसूचित किए जाते हैं।

टिप्पणी-2.—अन्यथा सुसहित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अर्हताएं आयु के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेंगी।

अनिवार्य अर्हताएं:

- (1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/स्कूल शिक्षा बोर्ड से मैट्रिक पास अथवा इसके समतुल्य। अथवा सेना का विशेष प्रमाण-पत्र।
- (2) भारतीय सेना से निर्मुक्त/सेवा मुक्त अधिकारी से भिन्न लेफ्टिनेन्ट पद पर (सम्मानिक के रूप में) कम से कम तीन वर्ष कमीशन अधिकारी रहा हो। अथवा नियमित रूप से सेवारत नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षक/मुख्य प्रशिक्षक/प्रशासनिक अधिकारी प्लाटून कमाण्डर/सहायक भंडार अधिकारी जो उक्त रूप में हिमाचल प्रदेश गृह रक्षा या नागरिक सुरक्षा में पांच वर्ष से सेवारत हो।

वांछनीय अर्हताएं:

- (1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि।
- (2) हिमाचल प्रदेश की रुठियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विलक्षण दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधो भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित प्रायः और नैतिक ग्रहण प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं।
 9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
- अपुः लागू नहीं।
 अनिवार्य ग्रहणः जैसी कि मद संख्या 7 (1) में दर्शित है।
- दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।
- 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा
 50 प्रतिशत सीधो भर्ती द्वारा।
10. भर्ती की पद्धति—भर्ती सीधो होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरो जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
- 50 620—1200 के वेतनमान में कार्यरत नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षक/मुद्र प्रशिक्षक/प्रशासनिक अधिकारी/पलाटून कमांडर/सहायक भण्डार अधिकारी जो सीधो भर्ती के लिए अनिवार्य ग्रहण रकता हो, क साथ जिनका उक्त रूप में कम से कम 5 वर्ष का नियमित या तदर्थ (31-12-83 तक) या तदर्थ सहित नियमित सेवाकाल हो, प्रोन्नति द्वारा।
- प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए ग्रेड में सेवाकाल के आधार पर एक संयुक्त ज्येष्ठता सूची तैयार की जाएगी।
11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियाँ, जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाएगा।
- हो 620—1200 के वेतनमान में कार्यरत नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षक/मुद्र प्रशिक्षक/प्रशासनिक अधिकारी/पलाटून कमांडर/सहायक भण्डार अधिकारी जो सीधो भर्ती के लिए अनिवार्य ग्रहण रकता हो, क साथ जिनका उक्त रूप में कम से कम 5 वर्ष का नियमित या तदर्थ (31-12-83 तक) या तदर्थ सहित नियमित सेवाकाल हो, प्रोन्नति द्वारा।
- प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए ग्रेड में सेवाकाल के आधार पर एक संयुक्त ज्येष्ठता सूची तैयार की जाएगी।
- टिप्पणी-1.—प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व संभरण पद में 31-12-1983 तक की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथा विहित सेवाकाल के लिए, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, गणना में ली जायेगी:—
- (क) उन सभी मामलों में जहाँ कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (31-12-1983) तक की गई कुल तदर्थ सेवा को शामिल करके के आधार पर उपर्युक्त निदिष्ट उपबन्धों के कारण विचार के लिए पात्र हो जाता है, वहाँ उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार के लिए पात्र समझे जायेंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रहे जायेंगे:
- परन्तु प्रोन्नति के लिए विचार किये जाने वाले सभी पदधारियों की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम ग्रहण सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होनी चाहिए:
- परन्तु यह और भी कि, जहाँ कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तु की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहाँ उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जायेगा।
- (ख) इसी प्रकार, स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित
- नियुक्ति से पूर्व 31-12-1983 तक की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जायेगी:
- परन्तु स्थायीकरण के परिणामस्वरूप तदर्थ सेवा को गणना में लेकर पारस्परिक ज्येष्ठता अपरिवर्तित रहेगी।
- (ग) 31-12-1983 के पश्चात् की गई तदर्थ सेवा, प्रोन्नति/स्थायीकरण के प्रयोजन के लिए हिसाब में नहीं ली जायेगी।
- टिप्पणी-2.—जब कभी नियम 2 के अनुसार पदों में बढ़ोतरी होती है तो नियम 10 और 11 के उपबन्ध सरकार द्वारा लोक सेवा आयोग के परामर्श से पुनरीक्षित किए जाएंगे।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना।
- जैसी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाएगी।
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
- जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित है।
14. सीधो भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षा।
- किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी निम्नलिखित अवश्य होना चाहिए:—
- (क) भारत का नागरिक, या
 (ख) नेपाल की प्रजा, या
 (ग) भूटान की प्रजा, या
 (घ) तिब्बती शरणार्थी, जो 1 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत में स्थायी निवास के आशय से आया हो, या
 (ङ) भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जिसने पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी पकोष्ठा के देशों कीनिया, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (भूतपूर्व तान्जानिया और जजीबार), नाइजीरिया, मालावी, जेयरे और डोमिनियन में भारत में स्थायी निवास के आशय से प्रवास किया हो:
- परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) और (ङ) के अभ्यर्थी ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।
- ऐसे अभ्यर्थी को, जिनके नामने में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा तालिम परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश किया जा सकेगा, किन्तु उसे नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा उसे आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के पश्चात् ही दिया जाएगा।
15. सीधो भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन।
- सीधो भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर और यदि यथास्थिति हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकारी ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर पाठ्यक्रम, यथास्थिति, आयोग/अन्य प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

16. आरक्षण

उक्त सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/पिछड़े वर्ग और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. शिथिल करने की शक्ति

जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह कारणों को अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

आदेश द्वारा,
कवर शमशेर सिंह,
सचिव।

[Authoritative English text of notification No. Home-II(B) 2-3/81, dated 15th February, 1987 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 15th February, 1987

No. Home-II (B) 2-3/81.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Company Commander/Senior Instructor/Store Officer in the Department of Home Guards, Civil Defence and Fire Services, Himachal Pradesh as per Annexure "A" attached to this notification, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Home Guards, Civil Defence and Fire Services Department Company Commander/Senior Instructor/Store Officer Recruitment and Promotion Rules, 1988.

(ii) These shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. **Rules.**—The number of posts, classification, pay scale, qualification and method of recruitment etc. for the post of Company Commander/Senior Instructor/Store Officer shall be specified in the Annexure "A".

3. **Repeal and savings.**—The Recruitment and Promotion Rules for the post of Company Commander/Senior Instructor/Store Officer notified by this Department notification No. 17-4/66-Home, dated the 30th January, 1971 are hereby repealed:

Provided that such repeal shall not effect the previous operation of the aforesaid rules or any appointment made or any action taken thereunder.

ANNEXURE-A

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF COMPANY COMMANDER/SENIOR INSTRUCTOR/STORE OFFICER IN THE DEPARTMENT OF HOME GUARDS AND CIVIL DEFENCE HIMACHAL PRADESH

1. Name of the post Company Commander/Senior Instructor/Store Officer.
2. Number of posts Company Commander=15, Senior Instructor=1, Store Officer=1.
Total posts=17.
3. Classification Class-III (Non-Ministrial)

4. Scale of pay Rs. 800-25-850/30-1000/40-1200/50-1400.
5. Whether selection post or non-selection post. Non-selection
6. Age for direct recruitment. 18 to 50 years:

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on *ad hoc* or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on *ad hoc* basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such *ad hoc* or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/other categories of persons to the extent permissible under the general or special order of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the public sector corporations and autonomous bodies who happened to be Government servants before absorption in the public sector corporations/autonomous bodies at the time of initial constitution of such corporations/autonomous bodies, shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the public sector corporations/autonomous bodies who were/are subsequently appointed by such corporations/autonomous bodies and are/were finally absorbed in the service of such corporations/autonomous bodies after initial constitution of the public sector corporations/autonomous bodies.

Note-1.—Age limit for direct recruitment will be reckoned in the first day of the year in which the posts are advertised for inviting applications or notified to the employment exchanges, as the case may be.

Note-2.—Age and experience in the case of direct recruitments relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission, in case the candidates otherwise well qualified.

- Essential qualifications:**
- (i) Should have passed Matriculation examination from recognised Board of School Education/University or its equivalent; or Should possess Army Special Certificate.
 - (ii) Should be a released/retired officer of the

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruits.

Indian Army who has held the rank of Lieutenant (other than Honorary) with at least three years service as a Commissioned Officer; or

Should be a serving regular Civil Defence Instructor/Chief Instructor/Administrative Officer/Platoon Commander/Assistant Store Officer who has been serving as such for the last five years in the Himachal Pradesh Home Guards and Civil Defence Department.

Desirable qualifications :

- (i) Graduate from a recognised University.
- (ii) Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

Age: No.

Educational qualifications:

As given in Col. No. 7(i)

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of pro-tees.

9. Period of probation, if any.

Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

50% by promotion;

50% by direct recruitment.

10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation/transfer and the percentage of vacancies to be filled in by various methods.

- 11 In case of recruitment by promotion, deputation/transfer, grades from which promotions, deputation/transfer is to be made.

By promotion from amongst Civil Defence Instructors/Chief Instructor/Administrative Officer/Platoon Commander/Assistant Store Officer working in the pay scale of Rs. 620-1200 possessing the essential qualification as prescribed for direct recruits with at least 5 years regular service or *ad hoc* (rendered upto 31-12-1983) service or both as such.

For the purpose of promotion a combined seniority list will be drawn on the basis of length of service in the grade.

Note 1.—In all cases of promotion *ad hoc* service rendered in the feeder post upto 31-12-1983, if any prior to the regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition:—

- (a) That in all cases where a junior person becomes eligible for

consideration by virtue of his total length of service (including *ad hoc* service rendered upto 31-12-1983) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category of post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior persons in the field of consideration :

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

- (b) Similarly, in all cases of confirmation, *ad hoc* service rendered in the post upto 31-12-1983, if any prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service:

Provided that the *inter se* seniority as a result of confirmation after taking into account *ad hoc* service shall remain unchanged.

- (c) *Ad hoc* service rendered after 31-12-1983 shall not be taken into account for confirmation/promotion purposes.

Note-2.—Provisions of rules 10 and 11 are to be revised by the Government in consultation with the Commission as and when the number of posts under rule 2 are increased.

As may be constituted by the Government from time to time.

As required under the law.

A candidate for appointment to any service or post may be,—

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.

14. Essential requirements for a direct recruitment.

- (a) a citizen of India, or
- (b) a subject of Nepal, or
- (c) a subject of Bhutan, or
- (d) a Tibetan refugee, who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India, or
- (e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.

Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of *viva voce* test and if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test, or by a practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Commission/other recruiting authority, as the case may be.

16. Reservation

The appointment to this service shall be subject to orders regarding reservation in the service for scheduled castes/scheduled tribes/backward classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Power to relax

Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

By order,
KANWAR SHAMSHER SINGH,
Secretary.

कल्याण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 29 सितम्बर, 1989

संख्या कल्याण (ए)-3-1/88. —राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश वृद्धों,

अपंगों तथा विधवाओं को पेंशन देने से सम्बन्धित नियमों को पारित करने के हैं :-

व्याख्या :

1. यह नियम हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा (पेंशन) नियम, 1989 कहलाएंगे।

यह नियम सारे हिमाचल प्रदेश में इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से लागू माने जाएंगे।

उद्देश्य :

2. इन नियमों का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत उन वृद्धों, अपंगों तथा विधवाओं को आर्थिक सहायता देना है, जिनके पालन-पोषण एवं देख-रेख का उचित साधन न हो।

पात्रता :

3. इन नियमों के अन्तर्गत निम्नलिखित वृद्ध, अपंग तथा विधवाएं पात्र होंगे।

(i) वृद्ध :

ऐसे वृद्ध व्यक्ति जिनकी आय 60 साल या इससे अधिक हो, उनके पालन-पोषण एवं देख-रेख का उचित साधन न हो तथा सब बातों में उनकी वार्षिक आय 2000/- रुपये से अधिक न हो।

(ii) अपंग :

(क) ऐसे अपंग व्यक्ति जिनकी अपंगता 50 प्रतिशत या इस से अधिक हो जिनके पालन पोषण तथा देख-रेख का कोई साधन न हो तथा जिनकी वार्षिक आय 2000/- रुपये से अधिक न हो तथा अपंगता उनकी रोजी-रोटी कमाने में बाधक सिद्ध होती हो।

(ख) ऐसे अपंग वृद्ध जिनकी अपंगता 50 प्रतिशत या इससे अधिक हो तथा जिनके माता-पिता या दोनों ही न हों तथा माता-पिता की वार्षिक आय 2000/- रुपये से अधिक न हो।

(ग) ऐसे व्यक्ति जो मानसिक रूप से अविकसित तथा पागल हों, जिनके पालन-पोषण तथा देख-रेख का कोई साधन न हो, वह अपनी रोजी-रोटी कमाने में असमर्थ हों तथा उनकी वार्षिक आय 2000/- रुपये से अधिक न हो।

(ग-1) ऐसे व्यक्तियों की अपंग राहत भत्ता उनके माता-पिता अथवा अभिभावक (गार्डीयन) के माध्यम से दिया जाएगा।

(iii) विधवाएं :

ऐसी विधवाएं जिनका कोई भी जीवन निर्वाह का साधन अथवा देख-रेख करने वाला/वाली न हो और जिनकी वार्षिक आय सभी साधनों से 2000/- रुपये से अधिक न हो, विधवा पेंशन की पात्र होंगी।

(ख) ऐसी विधवाएं जिनका कोई भी जीवित व्यस्क पुत्र/अविवाहित पुत्री किसी राजस्व में न लगी हो तथा जिन की वार्षिक आय 2000/- रुपये से अधिक न हो।

4. परलोक :

(i) उपरोक्त व्यक्तियों को हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी होना आवश्यक होगा।

(ii) विधवाएं तथा अपंगों के मामले में कोई आय सीमा नहीं होगी।

(iii) भिवारी पेंशन पाने के पात्र नहीं होंगे। ऐसे अपराधी जिनके अपराधिक मामले पुलिस में दर्ज होंगे या जिनके मामले न्यायालय में चल रहे होंगे पेंशन के पात्र नहीं होंगे।

(iv) वृद्धावस्था पेंशन के प्राथियों के यदि व्यस्क लड़के आजी-विका कमा रहे हों और उनकी मासिक आय 1000/- रुपये से अधिक हो तो ऐसे व्यक्ति पेंशन के पात्र नहीं होंगे तथा उनके लड़कों को अपने वृद्ध माता-पिता का पालन-पोषण करना होगा।

(v) वृद्धों का दी जाने वाली पेंशन वृद्धावस्था पेंशन कहलाएगी, अपंगों का दी जाने वाली पेंशन अपंग राहत भत्ता कहलाएगा तथा विधवाओं को दी जाने वाली पेंशन विधवा पेंशन कहलाएगी।

5. पेंशन की दर :

प्रत्येक व्यक्ति को पेंशन 60/- रुपये प्रति मास की दर से या उस दर से जो सरकार समय-समय पर निर्धारित करेगी, दी जाएगी।

प्रार्थना-पत्र का देना :

6 (i) नियम 3 के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त करने के लिए प्रार्थना-पत्र फार्म पर प्रार्थी द्वारा सम्बन्धित जिले के जिला कल्याण अधिकारी या तहसील कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। पेंशन के फार्म उपरोक्त अधिकारियों के अतिरिक्त कल्याण विभाग के निदेशालय, जिलाधीशों के कार्यालय तथा पंचायत में मुफ्त उपलब्ध होंगे। तहसील कल्याण अधिकारी प्राथियों के प्रार्थना-पत्र पूर्ण करवाने में सहायता करेंगे।

(ii) 12 वर्ष की आयु से कम वाले अपंग बच्चों के प्रार्थना-पत्र उनके माता-पिता अथवा संरक्षक द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे।

(iii) प्रार्थी अथवा अभिभावक (गार्डीयन) को प्रार्थना-पत्र पर अपनी इच्छा व्यक्त करनी होगी कि वह पेंशन डाकघर में अपना एकाऊंट्स खोलवा कर जमा करवाना चाहता है या मनीग्रार्डर द्वारा प्राप्त करना चाहता है।

सत्यापन :

7(i) जिला कल्याण अधिकारी अथवा तहसील कल्याण अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर उसे एक रजिस्टर में तुरन्त दर्ज किया जाए तथा प्रार्थना-पत्र को रजिस्टर का क्रमांक सीपा जाए। यह रजिस्टर अनुबन्ध पेंशन फॉर्म-2 के प्रपत्र पर रखा जाएगा। अधिकारी तुरन्त प्रार्थी को प्रार्थना-पत्र की पावती भेजेगा तथा उसमें उसके प्रार्थना-पत्र का क्रमांक देते हुए सुझाव देगा कि भविष्य में पत्राचार करते समय उस क्रमांक का ब्योरा वहां दिया जाए। साथ ही यदि प्रार्थना-पत्र में कोई त्रुटि रह गई हो तो उसे या तो स्वयं पूर्ण करवा ले या प्रार्थी को पूर्ण कराने हेतु लिख देगा। यह अधिकारी प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में दिए गए तथ्यों का सत्यापन महिला मण्डल तथा ग्राम पंचायत के प्रधान/सचिव की सहायता से करेगा। जहां आवश्यक होगा राजस्व विभाग के अधिकारियों का भी सहयोग प्राप्त किया जाएगा। आयु के बारे में शक होने पर वह आयु के बारे में प्रमाण-पत्र लिखित रूप में प्राप्त करेंगे। प्रार्थी को आयु के बारे में भूमि या मकान आदि से यदि हो तो उसने जो वास्तविक आय प्रार्थी को प्राप्त हो रही होगी वहां आय उद्गोस्त अधिकारियों द्वारा निश्चित की जाएगी।

(ii) ग्राम व्यक्तियों तथा वच्चों के बारे में निकटतम सरकारी अस्पताल या डिस्पेंसरी के चिकित्सा अधिकारी से प्रमाण-पत्र प्रार्थी प्रार्थना-पत्र के साथ लगाएगा या जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी प्राप्त करेगा।

(iii) विधवाओं के विधवा होने का प्रमाण-पत्र सम्बन्धित पंचायत या नगरपालिका ने प्राप्त किया जाएगा। इस प्रकार का प्रमाण-पत्र विधवाओं को प्रति वर्ष जिला कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा जिससे यह स्पष्ट हो सके कि विधवा ने पुनर्विवाह नहीं किया है।

पेंशन स्वीकृति हेतु कार्यविधि :

8. तहसील कल्याण अधिकारी प्राप्त प्रार्थना-पत्र का मौके पर जा कर व्यक्तिगत रूप से सत्यापन करने के उपरान्त अपनी रिपोर्ट प्रार्थना-पत्र पर देगे। यह रिपोर्ट नियम 7 (1) में दिए गए रजिस्टर में भी दर्ज की जाएगी जहां प्रार्थी पेंशन का पात्र नहीं पाया जाएगा वहां अधिकारी प्रार्थी को प्रार्थना-पत्र का क्रमांक देते हुए पात्र न होने के विवरण सहित, तुरन्त सूचित करेगा। जहां प्रार्थी पेंशन के पात्र पाए जाएंगे वहां रजिस्टर के क्रमांक अनुसार प्राथमिकता निर्धारित करते हुए अपनी सिकारिश सहित प्रस्ताव तहसील कल्याण अधिकारी/जिला कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। जिन प्रार्थना-पत्रों का सत्यापन जिला कल्याण अधिकारी द्वारा स्वयं किया गया होगा उन पर जिला कल्याण अधिकारी अपने कार्यालय में ही उपरोक्त कार्यवाही करेगा। मारे जिले के प्रार्थना-पत्र सुकलित करके रजिस्ट्रारों में दिए प्राथमिकता के आधार पर उनकी सूची जिला कल्याण अधिकारी द्वारा तैयार की जाएगी तथा यह सूची जिला कल्याण समिति के समुख समिति की बैठक में विचारार्थ तथा निर्णय हेतु प्रस्तुत की जाएगी। जिला कल्याण समिति द्वारा जो निर्णय लिए जाएंगे वह उस सूची में प्रत्येक व्यक्ति के नाम के आगे लिखे जाएंगे।

पेंशन का वितरण त्रैमासिक किया जाएगा जोकि त्रैमास के आरम्भ में ही किया जाएगा।

पेंशन स्वीकृति की शक्तियां :

9. पेंशन की स्वीकृति को शक्ति सम्बन्धित जिला के जिलाधीशों को होगी जोकि जिला कल्याण समिति द्वारा दिए गए निर्णयों के अनुसार तुरन्त स्वीकृति जारी करेंगे। जिला कल्याण समिति के लिए गए निर्णय अन्तिम होंगे तथा जिलाधीश उनमें कोई फेर बदल नहीं करेंगे। जिलाधीशों के साथ-साथ निदेशक, समाज एवं महिला कल्याण विभाग भी पेंशन स्वीकृति करने में सक्षम होंगे। पांगी तथा स्पिति में यह शक्तियां क्रमशः स्थानांतरित आयुक्त तथा अतिरिक्त जिलाधीश में निहित होगी। पेंशन सम्बन्धी समस्त रिकार्ड सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारियों/तहसील कल्याण अधिकारियों पांगी व काजा के कार्यालय में हो रहेंगे। स्वीकृति उपरान्त स्वीकृति की प्रति महालेखाकार,

हिमाचल प्रदेश सरकार (अवर सचिव, कल्याण तथा अवर सचिव, वित्त), समाज एवं महिला कल्याण सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी तथा तहसील कल्याण अधिकारी एवं कोषाधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी। तहसील कल्याण अधिकारी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् स्वीकृत पेंशनों का विवरण सम्बन्धित पंचायतों को भी इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत करेगा कि पंचायत समय-समय पर पेंशनरों की आर्थिक स्थिति के बारे में उसे सूचित करती रहेगी तथा दुर्भाग्यवश यदि पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो उसके बारे में तुरन्त सूचना प्रस्तुत करेगी। तहसील कल्याण अधिकारी पेंशनरों को भी पेंशन स्वीकृति के बारे में सूचित करेगा तथा नियम 7 (1) में दिए गए रजिस्टर में स्वीकृति का विवरण दर्ज करेगा। यदि उस पेंशनर की वित्तीय स्थिति पात्रता में दिए गए नियमों के प्रतिकूल न हो तो स्वीकृत पेंशन जीवन पर्यन्त लागू रहेगी।

पेंशन का वितरण :

10. पेंशन का वितरण त्रैमास आरम्भ होने पर किया जाएगा। सक्षम अधिकारी द्वारा पेंशन स्वीकृत किए जाने पर जिला कल्याण अधिकारी पेंशन की राशि का आहरण खजाने से करके मनीग्रार्डर द्वारा पेंशनर को भेज देगा या उसके डाकघर खाते में जमा करवा देगा जैसा कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना-पत्र में चाहा हो। पेंशन त्रैमास आरम्भ होने पर भेजी जाएगी। मनीग्रार्डर का व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा तीन मास समाप्त होने के तुरन्त पश्चात् अगल तीन मास को पेंशनर इस प्रकार पेंशनरों को अग्रिम रूप से भेज दी जाएगी या उनके खाते में जमा करवा दी जाएगी परन्तु पेंशन की राशि भेजने से पहले, पहली तिमाही में भेजी गई राशि की रसीद प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यदि किसी कारणवश मनीग्रार्डर वापिस आ जाए तो पुनः मनीग्रार्डर सरकार के खर्च पर भेज जाए। यदि पेंशनर की मृत्यु अग्रिम पेंशन प्राप्त करने के उपरान्त तीन मास समाप्त होने से पूर्व ही हो जाये तो ऐसे मामलों में अधिक दी गई राशि की वसूली नहीं की जाएगी।

पेंशन का बन्द किया जाना :

11. स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी, जिला कल्याण अधिकारी, तहसील कल्याण अधिकारी को यह ज्ञात हो जाए कि किसी व्यक्ति को पेंशन गलती से या गलत सूचना के आधार पर स्वीकृत हुई है या जिन परिस्थितियों के आधार पर पेंशन दी गई थी वह अब नहीं रही है तो वह उस पेंशनर का पूरा विवरण जिला कल्याण समिति के सम्मुख प्रस्तुत करेगा तथा जिला कल्याण समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार ही पेंशन जारी रखी या बन्द की जाएगी। ऐसे मामलों में जो पेंशन वितरित हो चुकी होगी, उसकी वसूली नहीं की जाएगी परन्तु गलत सत्यापन करने के लिए अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विभाग द्वारा की जाएगी। मृत्यु के मामले में पेंशन जिला कल्याण अधिकारी द्वारा स्वयं ही बन्द कर दी जाएगी तथा इसकी सूचना जिला कल्याण समिति को जब भी समिति की आगामी बैठक हो उसमें प्रस्तुत की जाएगी। इसी प्रकार विधवा के पुनर्विवाह की सूचना प्राप्त होने पर जिला कल्याण अधिकारी पेंशन बन्द करके विवरण जिला कल्याण समिति को आगामी बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा जिन मामलों में पेंशन बन्द की जाती है उनमें प्रभावित व्यक्ति छः मास के भीतर-भीतर निदेशक, (कल्याण) को अपनी अरील प्रस्तुत कर सकता है तथा निदेशक, (कल्याण) छानबीन करने पर जो निर्णय देगे वह अन्तिम होगा।

पते में परिवर्तन :

12. यह पेंशनर का दायित्व होगा कि यदि उसका पते में कोई परिवर्तन हो तो वह परिवर्तित पते की सूचना सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी तथा तहसील कल्याण अधिकारी को देगा। जो पेंशनर हिमाचल प्रदेश से बाहर 6 मास से अधिक समय तक रहगा सामान्यतः पेंशन का हकदार नहीं रहगा। परन्तु यदि वह स्वीकृति अधिकारी पेंशनर के प्रदेश से बाहर रहने की परिस्थितियों से मनुष्य हो तो वह पेंशन जारी रखने में सक्षम होगा यदि पेंशनर 2 मास से भी अधिक समय तक प्रदेश से बाहर रहे तो उसकी पेंशन जिला कल्याण समिति में निर्णय प्राप्त करने के उपरान्त बन्द कर दी जाएगी।

नियम कालिक जांच :

13. स्वीकृत पेंशनरों की समय-समय पर सम्बन्धित

जिला कल्याण अधिकारी अथवा तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा जांच की जाती रहेगी। जब भी अधिकारी प्रवास पर जाएंगे तो वह उस क्षेत्र में पेंशनर की आर्थिक स्थिति की जानकारी पंचायत तथा महिला मण्डल के सहयोग से प्राप्त किया करेंगे तथा प्राप्त की गई जानकारी नियम 7(1) में दिए गए रजिस्टर में दर्ज की जाएगी।

द्वितीय भाग

लेखांकन कार्यविधि :

14. प्रार्थना-पत्र की प्राप्ति पर उसे नियम 7(1) में दिए गए रजिस्टर में जिला कल्याण अधिकारी अथवा तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा दर्ज करके प्रार्थना-पत्र को स्थाई क्रमांक देकर पावती प्रार्थी को भेजी जाएगी।

प्राथमिकता :

15. नियम में वर्णित 3 प्रकार की पेंशनों का अलग-अलग प्राथमिकता उनके प्रार्थना-पत्रों की प्राप्ति की तिथि के आधार पर निर्धारित की जाएगी तथा यदि वजत में धनराशि कम उपलब्ध हो तो पेंशनर के पेंशन के प्रार्थना-पत्र अधिक हो तो बाद में प्राप्त हुए प्रार्थना-पत्रों को लम्बित रखा जाएगा। रजिस्टर में दर्ज तिथि के आधार पर प्राथमिकता में कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा।

16. किसी भी न्यायालय द्वारा की गई कुड़की इस पर लागू नहीं होगी।

17. प्रत्येक स्वीकृत पेंशनर का विवरण निजी लेजर खाते में फार्म पेंशन 3 में रखा जाएगा जिसमें प्रति 6 माह में किया गया भुगतान का विवरण भी दर्ज किया जाएगा।

18. प्रत्येक मनीआर्डर पर शब्द, हिमाचल प्रदेश, वृद्धावस्था पेंशन, अपंग राहत भत्ता/विधवा पेंशन जो लागू होगा अंकित होगा जैसे 3 मास की पेंशन भेजी जा रही है उसकी अवधि एवं दर भी अंकित होगी। मनीआर्डर भेजने से पहले आहरण तथा वितरण अधिकारी यह भली-भांति जांच लेगा कि पेंशनर का ठीक नाम व पता उसमें दिया गया है। वही अधिकारी निजी लेजर लेखा तथा उसमें सत्यापन के बाद हस्ताक्षर करने का जिम्मेवार भी होगा।

19. यदि पेंशनर अनपढ़ हो तो मनीआर्डर का भुगतान किसी पढ़े-लिखे व्यक्ति की मौजूदगी में किया जाएगा जोकि मनीआर्डर पर गवाही देगा। जिस पर पेंशनर का अंगूठा लगेगा। यदि कोई पेंशनर किसी कारण मनीआर्डर का अंगूठा/उंगलियों के चिन्ह नहीं लगा सकता तो उसकी राशि का भुगतान डाकघर विभाग के नियमों के अनुसार किया जाएगा। 12 साल से कम आयु वाले बच्चों को पेंशन का भुगतान उनके माता-पिता या संरक्षक को किया जाएगा। परन्तु 6 मास में जिला कल्याण अधिकारी द्वारा निजी लेजर लेखा का निरीक्षण किया जाएगा तथा जिन वृद्धों/अपंग/विधवाओं की पेंशन की अदाएनी नहीं की गई होगी उनकी छानबीन होगी तथा प्राप्त रसीदों को लेजर के उपयुक्त कालम में दर्ज कर उस पर "कैसल्ड" की मोहर लगा कर क्रम बार सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी को कार्यालय में रखा जाएगा। यदि पेंशनरों की रसीद आने में 45 दिन से अधिक का समय लग जाए या भुगतान नहीं होने के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हो जाए तो आहरण तथा वितरण अधिकारी डाकघर विभाग के साथ मामले को उठाएगा और इसमें एक मास के अन्दर-अन्दर अन्तिम निर्णय लेकर पेंशनर को तथ्यों से अवगत करवाएगा तथा पेंशन के भुगतान का प्रबन्ध करवाएगा। पेंशनर के मनीआर्डर की रसीदें सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में भली प्रकार दो वर्ष या जब तक ऑडिट नहीं हो जाए तब तक सुरक्षित रखी जाएगी। पेंशन योजना की वितरित धनराशि की लेखा परीक्षा महालेखाकार (लेखा परीक्षा), हिमाचल प्रदेश, शिमला-3 द्वारा की जाएगी।

20. धनराशि की बड़ी मात्रा में नकद रूप में ले जाने की वजाय जहां तक सम्भव हो इसे डाकघर विभाग को धनराशि बैंक ड्राफ्ट/बैंक द्वारा दी जाया करेगी।

बिना भुगतान की राशि :

21. आहरण तथा वितरण अधिकारी ऐसे मनीआर्डर की राशि

को बिना भुगतान के वापिस आएगी को स्वयं प्राप्त करेगा यदि किसी कारणवश वह कार्यालय में न हो तो यह राशि मुख्यालय के तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाएगी तथा जिला कल्याण अधिकारी के आने पर उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और इस राशि का विवरण अलग रजिस्टर खोल कर पेंशन फार्म-4 पर रखा जाएगा।

22. रजिस्टर पर दर्ज विवरण आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा जो धनराशि बिना वितरण के वापिस प्राप्त होगी उसे रोकड़ में लिया जाएगा। यदि इस राशि को दोबारा पेंशनर को नहीं भेजा जाना हो तो समस्त राशि जो वापिस हुई है उसके अगले 3 मास के विल में शार्ट ड्राल द्वारा समायोजन किया जाएगा।

23. सम्बन्धित जिलों के जिला कल्याण अधिकारी 6 माह में पेंशन का वितरण करने के तुरन्त उपरान्त पेंशन वितरण रिपोर्ट जून माह व दिसम्बर के अन्त में पेंशन फार्म-5 पर निदेशालय, समाज एवं महिला कल्याण को प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ ही मास लम्बित पेंशन मामलों का विवरण भी फार्म पेंशन 6 पर प्रस्तुत किया जाएगा। परन्तु जिला के जिला कल्याण अधिकारी व तहसील कल्याण अधिकारी के माध्यम से अपने जिले में तीनों प्रकार की पेंशनों के पात्र व्यक्तियों का सर्वेक्षण करवायेगा तथा सर्वेक्षण रिपोर्ट फार्म-7 पर निदेशक, समाज एवं महिला कल्याण को प्रति वर्ष 31 दिसम्बर तक प्रस्तुत की जाएगी।

24. निदेशक, समाज एवं महिला कल्याण विभाग पेंशन योजना के प्रमुख इन्चार्ज होंगे। वह इस योजना को ठीक रूप में कार्यान्वित करने हेतु समय-समय पर उचित आदेश जारी करेंगे।

लेखा शीर्ष :

25. वृद्धावस्था पेंशन तथा अपंग राहत भत्ता तथा विधवा पेंशन का व्यय मनीआर्डर कमीशन सहित निम्न लेखा शीर्ष या सरकार द्वारा निर्धारित लेखा शीर्ष से किया जाएगा।

वृद्धावस्था पेंशन/अपंग/राहत भत्ता :

(I) 2235—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण—02 समाज कल्याण—102 सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत पेंशन-01 वृद्धावस्था पेंशन (गैर-योजना)।

विधवा पेंशन :

(II) 2235—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण—02 समाज कल्याण—102 सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत पेंशन-02 विधवाओं को पेंशन (गैर-योजना)।

इन पेंशनों से सम्बन्धित नियमों जो अधिसूचना सं० 12-2/71-बैल-सकट, दिनांक 28-2-73 तथा कल्याण क-3-4/79, दिनांक 26-2-80 द्वारा अधिसूचित किए गए हैं उन नियमों के अधीन दिए गए निर्णय नियमित समझ जाएंगे तथा बाद के सम्शोधनों द्वारा अधिसूचित किए गए नियम इस अधिसूचना के जारी होने के साथ-साथ निश्चित समझ जाएंगे।

पेंशन फार्म-1

कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

वृद्धावस्था पेंशन/अपंग राहत भत्ता, विधवा पेंशन के लिए प्रार्थना-पत्र।

1. प्रार्थी का नाम
2. पिता/पति का नाम
3. यदि पिता/पति जीवित नहीं हैं तो संरक्षक का नाम व उससे नाता
4. जाति
5. आय
6. शिनाखती चिन्ह

7. वर्तमान रिहायश का पता
8. स्थाई पता
9. पता जहाँ प्रार्थी पिछले चार वर्षों से रह रहा है
10. माता/पिता/पति में कौन जीवित है
11. भाप कैसे जीवन निर्वाह कर रहे हैं
12. क्या स्थाई या अस्थायी रूप से अपंग है। अपंगता का व्यौरा तथा अपंगता की प्रतिशता क्या है। प्रमाण-पत्र चिकित्सा अधिकारी/इंचार्ज राजकीय चिकित्सालय/सिविल डिस्पेंसरी से प्राप्त कर संलग्न किया जाए।

13. आश्रित सदस्यों की सूची

क्र०सं०	नाम	आयु	नाता	व्यवसाय
1	2	3	4	5

तहसील, जिला, हिमाचल प्रदेश का/की स्थाई निवासी है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती पुत्र/पुत्री ग्राम, डाकघर, तहसील, जिला की मासिक/वार्षिक आमदनी समस्त स्रोतों से रुपये है और न ही इसका कोई कमाने वाला है।

3. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती की आयु वर्षों में वर्ष है।

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती को विभाग द्वारा पहले पेंशन स्वीकृत नहीं की गई है।

हस्ताक्षर मोहर सहित
जिला कल्याण अधिकारी,
तहसील कल्याण अधिकारी।

पेंशन फॉर्म-2

14. समस्त स्रोतों से मासिक आय
15. प्रार्थी की शिक्षा
16. क्या प्रार्थी को किसी प्रकार की सहायता पेंशन इत्यादि सरकार से मिलती है यदि मिलती है तो कहां से और कितनी

17. सम्पत्ति की व्याख्या और उसकी कीमत :-

- (क) भूमि अन्दाजन
- (ख) बैंक में जमा राशि व डाकघरों के वजट खाते में जमा राशि का विवरण।

- (ग) राजकीय स्किम/रिट्टी में लगाया गया धन
- (घ) अन्य साधनों से आमदनी
- (ङ) कुल सालाना आमदनी

18. दो व्यक्तियों के नाम व पूरा पता जो प्रार्थी को भली भांति जानते हों और प्रार्थी की वास्तविकता को बतला सकें।

1. नाम व पता :
2. नाम व पता :

प्रार्थी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
(पैड स्थाई के साथ)

घोषणा

मैं पुत्री/पुत्र/पत्नी ग्राम, डाकघर, तहसील, जिला, मर्यादा निष्ठा लेकर अपने ज्ञान से अभिपुष्टि पूर्वक यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि उक्त तथ्य मेरे प्रतिज्ञान से सही है। इसमें कोई भी तथ्य असत्य नहीं है और न ही इसमें कोई बात छपाई गई है। मैं यह भी पुष्टि करता हूँ/करती हूँ कि इससे पूर्व मैं कोई पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा हूँ/रही हूँ।

प्रार्थी के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान
(पैड की स्थाई के साथ)

सत्यापन रिपोर्ट

जिला कल्याण अधिकारी,
तहसील कल्याण अधिकारी।

प्रमाण-पत्र

नीचे लिखे प्रमाण-पत्र जिला कल्याण अधिकारी/तहसील/कल्याण अधिकारी द्वारा जारी किए जाएंगे :-

1. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती पुत्र/पुत्री ग्राम, डाकघर

क्र०सं० प्रार्थी का नाम व पता पेंशन फॉर्म पावती पावती पत्र अधिकारी की तिथि भेजने की तिथि सत्यापन विवरण

1 2 3 4 5

सत्यापन द्वारा प्राप्त पाया गया या नहीं यदि प्राप्त नहीं पाया गया तो उत्तर भेजने की तिथि जिस अधिकारी द्वारा सिफारिश की गई जिसके अन्तर्गत पेंशन स्वीकृत की गई

6 7 8 9

नियमित निरीक्षण की तिथि निरीक्षण का परिणाम विवरण

10 11

पेंशन फॉर्म-3

अधिकारी जिस द्वारा पेंशन स्वीकृत की गई खाता सं० पेंशनर का नाम जाति पिता/पति का नाम ग्राम डा०, तह०, जिला

क्र०सं० पेंशन की दर तिथि जिसे पेंशन स्वीकृत की गई स्वीकृत सं० व दिनांक अवधि जिसके लिए स्वीकृत देय है

1 2 3 4 5

अर्द्ध-वार्षिक की अवधि जिसके लिए पेंशन भेजी गई	पेंशन की राशि	मनीआर्डर रसीद सं० व दिनांक जिसको राशि भेजी गई	अधिकारी के हस्ताक्षर
6	7	8	9

पावती रसीद प्राप्त की तिथि	अधिकारी के हस्ताक्षर	पेंशन बन्द होने के कारण तथा तिथि
10	11	12

अधिकारी के हस्ताक्षर	विवरण
13	14

पेंशन फार्म-4

क्र०सं० पेंशनर का नाम व पता	व्यक्तिगत लैजर खाता नं०	जिस अर्द्ध वार्षिक का मनीआर्डर वापिस प्राप्त हुआ
1	2	3

राशि जो वापिस प्राप्त हुई	मनीआर्डर वापिस प्राप्त होने का कारण	आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर
5	6	7

यदि दोबारा मनीआर्डर भेजा गया है उसकी रसीद सं० व दिनांक	वापिस प्राप्त हुई राशि जिस तिथि को रोकड़ में दर्ज की गई का विवरण	अधिकारी के हस्ताक्षर
8	9	10

बिल सं० जिसके द्वारा वापिस प्राप्त हुई राशि का शार्ट ड्राल की गई	जिस अधिकारी के आदेशों के द्वारा शार्ट ड्राल की गई	आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर
11	12	13

पेंशन फार्म-5

..... से तक समाप्त होने वाले अर्द्ध वार्षिक की पेंशन वितरण रिपोर्ट ।

जिला का नाम

क्र०सं० पेंशन की किस्म	आवंटित पेंशनरों की सं०	अर्द्ध-वार्षिक समाप्त होने से पूर्व स्वी-कृत पेंशनरों की सं०	पिछले अर्द्ध-वार्षिक में मृत व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4

वर्तमान पेंशनरों की सं०	कालम 3 व 6 में भिन्नता	भिन्नता के कारण	पिछले अर्द्ध-वार्षिक में प्रतिस्वामी स्वीकृति द्वारा ली गई स्वीकृति की सं०
6	7	8	9

वर्तमान अर्द्ध वार्षिक में जितने व्यक्तियों को पेंशन भेजी गई	भुगतान जब आरम्भ किया गया, उसकी तिथि	भुगतान की अन्तिम तिथि	अर्द्ध वार्षिक में जितना खर्चा किया गया
10	11	12	13

स्वीकृत मामलों के अतिरिक्त जितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए	कालम 14 में प्राप्त प्रार्थना-पत्रों में से कितनों का सत्यापन किया गया व सही पाए गए	विवरण
14	15	16

पेंशन फार्म-6

पेंशन योजना के अन्तर्गत लम्बित प्रार्थना-पत्रों का अर्द्ध वार्षिक विवरण की समाप्त हो रहे अर्द्ध वार्षिक का विवरण ।

क्र०सं० योजना का नाम	पिछले अर्द्ध वार्षिक के अन्त में लम्बित प्रार्थना-पत्रों की संख्या	कुल सत्यापन किए गए	सत्यापन हेतु लम्बित है
1	2	3	4

योजना के अन्तर्गत इस
अर्द्ध वार्षिक में जिसकी
सूचना भेजी जा रही है
किन्तु प्राथना-पत्र
प्राप्त हुए।

कुल

सत्यापन न
करने का
कारण

क्या पूर्ण जिले का सर्वेक्षण किया गया या नहीं
यदि हाँ तो कारण तथा जिस क्षेत्र का
सर्वेक्षण नहीं किया गया उसका विवरण
पत्र व्यक्तियों के फार्म यदि
पूर्ण करवाए गए या नहीं यदि
नहीं तो कारण।

6

7

कुल सत्यापन किए गए सत्यापन हेतु
लम्बित है कुल सत्यापन
किये गए सत्यापन हेतु
लम्बित है

6

7

8

9

10

पेंशन फार्म-7

क्र० सं० पेंशन को वर्ष के लिए कुल स्वीकृत वर्ष के दौरान जिले में
किस्म निर्धारित पेंशनर पेंशनर जो सर्वेक्षण किया गया
उसमें पाए गए पत्र व्यक्तियों की संख्या

1

2

3

4

5

हस्ताक्षरित/-
सचिव।

भाग 4—स्थानीय स्वायत्त शासन: म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नोटिफाइड और टाउन एरिया तथा पंचायती राज विभाग
शुन्य

भाग 5—व्यक्तिगत अधिसूचनाएं और विज्ञापन

In the Court of Shri J. N. Barowalia, Senior Sub Judge,
Kangra at Dharamshala

No. SSJ/90.....
Dt.....

Civil Suit No. 249/1989

Titled as Smt. Magan Devi d/o Shri Manohar Singhat
present w/o Khem Bhalur, r/o Gabli Dar, Mauza Ghan-
ara, Tehsil Dharamshala District Kangra .. Plaintiff.

Versus

The general public etc.

Subject.—Proclamation in civil suit No. 249/1989
titled as Magan Devi versus the general public.

Whereas in the noted case the plaintiff has filed a
civil suit for declaration in this court.

Hence this proclamation is hereby issued to the general
public and kith and kins to file their objections, if any,
in this court on or before 25-4-1990 at 10 A.M. either
personally or through an authorised agent, failing which
the suit will be heard and allowed in favour of the appli-
cant

Given under my hand and seal of the court on the
19th March, 1990.

Seal. J. N. BAROWALIA,
Senior Sub Judge,
Kangra at Dharamshala.

In the court of Shri J. N. Barowalia, Senior Sub Judge,
Kangra at Dharamshala

Succession Case No. 2/90

Date of hearing : 23-4-1990

Saran Dass s/o Diwana Ran, r/o village Bamnehr,
Mauza Pathiar, P.O. Pothjar, Teh Palampur.. Petitioner.

Versus

1. General public.

2. Ratto Devi, 3. Smt. Kirtan Devi, 4. Smt.
Gohri Devi .. Respondent.

To
General public.

Whereas in the above noted case the petitioner have
filed an application in this court under section 9 of the
Guardian and Wards Act in respect of the appointment
of Guardian of minor Sujata Kumari d/o Prem Chant,
s/o Shri Julla Ram, village Bamnehr, P.O. Pathiar, Tehsil
and District Kangra.

Hence, this proclamation is hereby issued against the
general public of the illaqua kith and kins of the minor
to file objection, if any, to the grant of said Guardianship,
in this court on 23-4-1990 at 10.00 A.M. personally or
through pleader failing which the petition will be heard
and disposed of *ex parte*.

Given under my hand and seal of the court on this 12th
day of March, 1990.

Seal. J. N. BAROWALIA,
Senior Sub Judge,
Kangra at Dharamshala.

In the Court of Shri A. S. Jaswal, Sub Judge 1st Class (II),
Hamirpur, Himachal Pradesh

Civil Suit No. 77/89

Versus

8. Smt. Lohki Devi wd/o Tulsi r/o village Ser,
Tappa Dhaned, Tehsil and District Hamirpur,
Himachal Pradesh.

Whereas it has been proved to the satisfaction of this
court that the above named defendants cannot be served
in the ordinary course of service as she is evading the
service of summon issued against her.

Hence this proclamation under Order 5, Rule 20, C.P.C.
is hereby issued against her to appear in this court on
11-4-90 at 10.00 A.M. personally or through an authorised
agent to defend their case, failing which she will be
proceeded *ex parte*.

Given under my hand and the seal of the court this
7th day of March, 1990.

Seal. A. S. JASWAL,
Sub Judge 1st Class (II),
Hamirpur, H. P.

In the Court of Shri A. K. Sharma, Sub-Judge 1st Class,
Court No. II, Una, District Una, Himachal Pradesh

Civil Suit No. 67/1988

Pending for : 25-4-1990

Durga Dass son of Shri Mela Ram, caste Lohar, r/o
village Santokhgarh, Tehsil and District Una (H.P.)
.. Plaintiff.

Versus

Sant Ram son of Shri Mela Ram and others.

Suit for declaration

To

5. Khushi Ram son of Khazana Ram, resident of
Village Santokhgarh, District Una (H.P.).

Whereas in the above noted case, it has been proved to
the satisfaction of this court that the above named
defendant cannot be served in the ordinary course of
service as he is evading the service of summons issued
against him.

Hence this proclamation under Order 5, rule 20,
C.P.C. is hereby issued against him to appear in this
court on 25-4-1990 at 10.00 A.M. personally or through
an authorised agent or pleader to defend the case,
failing which will be proceeded *ex parte*.

Given under my hand and the seal of the court this
7th day of March, 1990.

Seal.

A. K. SHARMA,
Sub Judge 1st Class, Court No. II,
Una (H.P.).

ब अदालत श्री अनिल कुमार खाचो, उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट कांगड़ा
जिला कांगड़ा

श्री कुलदीप सिंह सुपुत्र श्री शमशेर सिंह, निवासी गांव व डाकखाना
समीरपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश .. प्राथी ।

बनाम

साधारण जनता

दरखास्त जेर घारा 13 (3) पंजीकरण जन्म व मृत्यु

उपरोक्त मुकदमा उनवान बाला में प्राथी श्री कुलदीप सिंह सुपुत्र
श्री शमशेर सिंह, निवासी समीरपुर, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा
ने इस कार्यालय में गुजारिश की है कि उसके सुपुत्र श्री सुनील
कुमार का जन्म दिनांक 28-9-1974 को हुआ है लेकिन उसकी
जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड समीरपुर में पंजीकृत नहीं हुई है ।

अतः ग्राम जनता को बजरिया इस्तहार राजपल सूचित किया
जाता है कि उपरोक्त पंजीकरण के बारा किसी को कोई उजर व
एतराज हो तो वह दिनांक 7-5-1990 को अमालतन या बकालतन
इस कार्यालय में सुबह 10 बजे हाजर आवें तथा उजर पेस करें
अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।

आज दिनांक 17-3-1990 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत
से जारी हुआ ।

मोहर ।

अनिल कुमार खाचो,
उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट,
कांगड़ा, जिला कांगड़ा ।

ब अदालत श्री अनिल कुमार खाचो, उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट, कांगड़ा,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री शमशेर सिंह, निवासी गांव व डाकखाना
समीरपुर, जिला कांगड़ा, हि० प्र० .. प्राथी ।

बनाम

साधारण जनता

दरखास्त जेर घारा 13 (3) पंजीकरण जन्म व मृत्यु ।

उपरोक्त मुकदमा उनवान बाला में प्राथी श्री कुलदीप सिंह
सुपुत्र श्री शमशेर सिंह, निवासी समीरपुर, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा ने
इस कार्यालय में गुजारिश की है कि उसके सुपुत्र श्री मनीश कुमार का
जन्म दिनांक 26-7-1979 को हुआ है लेकिन उसकी जन्म तिथि पंचायत
रिकार्ड समीरपुर में पंजीकृत नहीं हुई है ।

अतः ग्राम जनता को बजरिया इस्तहार राजपल सूचित किया
जाता है कि उपरोक्त पंजीकरण के बारा किसी को कोई उजर व
एतराज हो तो वह दिनांक 7-5-1990 को अमालतन या बकालतन
इस कार्यालय में सुबह 10 बजे हाजर आवें तथा उजर पेस करें
अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।

आज दिनांक 17-3-1990 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत
से जारी हुआ ।

मोहर ।

अनिल कुमार खाचो,
उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट, जिला कांगड़ा ।

ब अदालत श्री अनिल कुमार खाचो, उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट, कांगड़ा
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री कुलदीप सिंह सुपुत्र श्री शमशेर सिंह, निवासी गांव व डाकखाना
समीरपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश .. प्राथी ।

बनाम

साधारण जनता

दरखास्त जेर घारा 13 (3) पंजीकरण जन्म व मृत्यु ।

उपरोक्त मुकदमा उनवान बाला में प्राथी श्री कुलदीप सिंह पुत्र
श्री शमशेर सिंह, निवासी समीरपुर, तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा ने
इस कार्यालय में गुजारिश की है कि उसकी सुपुत्री सुषमा कुमारी का जन्म
दिनांक 19-6-1978 को हुआ है लेकिन उसकी जन्म तिथि पंचायत
रिकार्ड समीरपुर में पंजीकृत नहीं हुई है ।

अतः ग्राम जनता को बजरिया इस्तहार राजपल सूचित किया जाता
है कि उपरोक्त पंजीकरण के बारा किसी को कोई उजर व एतराज
हो तो वह दिनांक 7-5-1990 को अमालतन या बकालतन इस कार्यालय
में सुबह 10 बजे हाजर आवें तथा अपने उजर पेस करें अन्यथा दीगर
कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।

आज दिनांक 17-3-1990 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से
जारी हुआ ।

मोहर ।

अनिल कुमार खाचो,
उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट, कांगड़ा, जिला कांगड़ा ।

ब अदालत श्री बी० आर० जम्वाल हि० प्र० से०, सनाहती रोहडू
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री सन्त लाल पुत्र श्री जान चन्द, साकन जाखो, तहसील चढ़गांव,
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश .. फरीक अब्बल ।

बनाम

श्री धीरज राम आदि, वासी जाखो, तहसील चढ़गांव, जिला
शिमला, हिमाचल प्रदेश .. फरीक दोयम ।

नोटिस बनाम:

श्री जोऊलाल पुत्र श्री जान चन्द, निवासी जाखो, तहसील चढ़गांव,
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ।

अपील जेर धारा 114 (2) आफ हि० प्र० टैनेसी एण्ड लेण्ड रिकार्ड ऐक्ट ।

मुकद्दमा उपरोक्त उनवान वाला में फरीक दोयम जीऊ लाल पुत्र श्री जान चन्द, निवासी जाखी, तहसील चढ़गांव के नाम अदालत हुआ से कई बार समन तथा बजरिया पंजीकृत ए० डी० से भी समन भेजे गए । मगर इस पर तामील असालतन नहीं हो रही है और न वह अदालत में हाजिर हो रहा है । अदालत को यह यकीन हो चुका है कि उसकी तामील साधारण तौर पर नहीं हो सकती ।

अतः श्री जीऊ लाल उपरोक्त को बजरिया इशतहार राजपत्र सूचित किया जाता है कि अगर आपको उपरोक्त अपील के द्वारा कोई उजर व एतराज हो तो मिति 20-4-1990 को सुबह 10 बजे इस कार्यालय में असालतन या वकालतन हाजर होवे, अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

आज दिनांक 9-3-1990 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया है ।

मोहर ।

बी० आर० जम्वाल,
समाहर्ता, रोहड, जिला,
शिमला, हि० प्र० ।

व अदालत श्री आर० के० भाटिया, उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट, ऊना जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री बीरबल पुत्र श्री राम रखा, वासी सीड़दा, डाकखाना धुंधला, तहसील बगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

बनाम

ग्राम जनता

दरखास्त जेर धारा 13 (3) पंजीकरण जन्म व मृत्यु ।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री बीरबल पुत्र श्री राम रखा, गांव सीड़दा, डाकखाना धुंधला, तहसील बगाणा ने इस कार्यालय में गुजारिश की है कि उसकी पुत्री कमारी शशि देवी का जन्म दिनांक 2-2-1983 को हुआ है लेकिन उसकी जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में पंजीकृत नहीं हुई है ।

अतः ग्राम जनता को बजरिया इशतहार राजपत्र सूचित किया जाता है कि उपरोक्त पंजीकरण द्वारा किसी का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 19-4-1990 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में सुबह 10 बजे हाजर आवें तथा अपने उजर पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।

आज दिनांक 19-4-1990 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर ।

आर० के० भाटिया,
उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट, ऊना,
जिला ऊना, हि० प्र० ।

व अदालत श्री आर० के० भाटिया, उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट, ऊना जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती फिरोजी देवी बिबवा श्री दुर्गा दास, वासी याना कला, तहसील बगाणा, जिला ऊना, (हि० प्र०)

बनाम

ग्राम जनता

दरखास्त जेर धारा 13(3) पंजीकरण जन्म व मृत्यु ।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्रीमती फिरोजी देवी बिबवा श्री दुर्गा दास, वासी याना कला, तहसील बगाणा, जिला ऊना ने इस कार्यालय में गुजारिश की है कि उसकी दोती कुमारी रचना देवी

का जन्म दिनांक 26-1-1984 को हुआ है । लेकिन उसकी जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में पंजीकृत नहीं हुई है ।

अतः ग्राम जनता को बजरिया इशतहार राजपत्र सूचित किया जाता है कि उपरोक्त पंजीकरण के द्वारा किसी का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 19-4-1990 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में सुबह 10.00 बजे हाजर आवें तथा अपने उजर पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।

आज दिनांक 19-3-1990 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर ।

आर० के० भाटिया,
उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट, ऊना,
जिला ऊना, हि० प्र० ।

व अदालत श्री आर० के० भाटिया, उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट, ऊना जिला ऊना (हिमाचल प्रदेश)

श्री जसवीर सिंह पुत्र श्री अमृत सरिया, वासी कुठार बोट, उप-तहसील हरोली, जिला ऊना (हि० प्र०)

प्रार्थी ।

बनाम

ग्राम जनता

दरखास्त जेर धारा 13 (3) पंजीकरण जन्म व मृत्यु ।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री जसवीर सिंह पुत्र अमृत सरिया, वासी कुठार बोट, उप-तहसील हरोली ने इस कार्यालय में गुजारिश की है कि उसका पुत्र दीपक ठाकुर का जन्म दिनांक 27-8-1987 को हुआ है । लेकिन उसकी जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में पंजीकृत नहीं हुई है ।

अतः ग्राम जनता को बजरिया इशतहार राजपत्र सूचित किया जाता है कि उपरोक्त पंजीकरण के द्वारा किसी का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 19-4-1990 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में सुबह 10 बजे हाजर आवें तथा अपने उजर पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी ।

आज दिनांक 19-3-1990 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ ।

मोहर ।

आर० के० भाटिया,
उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट, ऊना,
जिला ऊना (हि० प्र०) ।

व अदालत श्री आर० के० भाटिया, उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट ऊना, जिला ऊना, (हिमाचल प्रदेश)

श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री किशन चन्द, निवासी मुहल्ला तेलियां, ऊना, (हि० प्र०) ।

प्रार्थी ।

बनाम

ग्राम जनता

दरखास्त जेर धारा 13 (3) पंजीकरण जन्म व मृत्यु ।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री किशन चन्द, वासी मुहल्ला तेलियां ने इस कार्यालय में गुजारिश की है कि उसके पुत्र टीका (Tikka) का जन्म दिनांक 19-1-1968 को हुआ है । लेकिन उसकी जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में पंजीकृत नहीं हुई है ।

अतः ग्राम जनता को बजरिया इशतहार राजपत्र सूचित किया जाता है कि उपरोक्त पंजीकरण के द्वारा किसी का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 19-4-1990 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में सुबह 10 बजे हाजर आवें तथा अपने उजर पेश करें

अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 19-3-1990 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

आर० के० भाटिया,
उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट, ऊना,
जिला ऊना (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री आर० के० भाटिया, उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट, ऊना,
जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री यज्ञ दत्त शर्मा पुत्र श्री मुन्गी राम, वासी बलियारा, तप्पा हेरू,
तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

बनाम

ग्राम जनता।

दरखास्त जेर धारा 13(3) पंजीकरण जन्म व मृत्यु।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में प्रार्थी श्री यज्ञ दत्त शर्मा पुत्र श्री मुन्गी राम, वासी बलियारा, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में गुजारिश की है कि उसकी पुत्री निधी शर्मा का जन्म दिनांक 6-6-1987 को हुआ है लेकिन उसकी जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में पंजीकृत नहीं हुई है।

अतः ग्राम जनता को बजरिया इशतहार राजपत्र सूचित किया जाता है कि उपरोक्त पंजीकरण के द्वारा किसी का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 9-4-1990 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में सुबह 10 बजे हाजर आवें तथा अपने उजर पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 7-3-1990 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

आर० के० भाटिया,
उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट,
ऊना, जिला ऊना, हि० प्र०।

ब अदालत श्री आर० के० भाटिया, उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट, ऊना,
जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती राम प्यारी पत्नी श्री कर्म चन्द, निवासी मलाहत नगर, ऊना,
जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

बनाम

ग्राम जनता।

दरखास्त जेर धारा 13(3) पंजीकरण जन्म व मृत्यु।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में प्रार्थी श्रीमती राम प्यारी पत्नी श्री कर्म चन्द, निवासी मलाहत नगर ऊना ने इस कार्यालय में गुजारिश की है कि उसकी पुत्री नीरज का जन्म दिनांक 14-3-1986 को हुआ है लेकिन उसकी जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में पंजीकृत नहीं हुई है।

अतः ग्राम जनता को बजरिया इशतहार राजपत्र सूचित किया जाता है कि उपरोक्त पंजीकरण के द्वारा किसी का कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 9-4-1990 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में सुबह 10 बजे हाजर आवें तथा अपने उजर पेश करें अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज तिथि 7-3-1990 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

आर० के० भाटिया,
उप-मण्डल मैजिस्ट्रेट,
ऊना, जिला ऊना, हि० प्र०।

ब अदालत जनाब बलदेव शर्मा, तहसीलदार व अखत्यारात सब-रजिस्ट्रार
हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं० 5 आफ 1989

श्रीमती सुखदेवी बेवा श्री शक्ति चन्द पुत्र बीरबल, वासी चलाखर,
मौजा मतिटीहरा

बनाम

ग्राम जनता

.. मसुलअलैहम्।

दरखास्त जेर धारा 40/41 वाकत रजिस्टर्ड करने दसीयतनामा
मुनयफी श्री शक्ति चन्द पुत्र बीरबल, वासी चलाखर, मौजा मतिटीहरा।

नोटिस बनाम ग्राम जनता।

उपरोक्त विषय पर हर ग्राम या खाम को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त बसीयत को रजिस्टर्ड करने में कोई उजर हो तो वह दिनांक 2-5-1990 को असालतन या वकालतन इस न्यायालय में हाजिर होकर इसकी परखी करें अन्यथा दीगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

हस्ताक्षर हमारे व मोहर अदालत में मिति 12-2-1990 को जारी हुआ।

मोहर।

बलदेव शर्मा,
तहसीलदार व अखत्यारात,
सब-रजिस्ट्रार, हमीरपुर।

In the Court of Shri Bhagwan Dass Madan, Executive
Magistrate, Indora, District Kangra (H. P.)

Shri Joginder Singh son of Shri Mahant Ram, resident
of village Malot, Tehsil Indora, District Kangra (H. P.)
.. Applicant.

Versus

General public

.. Respondent.

Application under section 13(3) of Registration Births
and Deaths Act, 1969.

To

The general public.

Whereas in the above-noted applicant have moved an
application duly supported with an affidavit under section
13(3) of Births and Deaths Registration Act, 1969 for
Registration of his daughter named Miss Mina Kumari
who was born on 22-12-1984 in village Malot, Tehsil
Indora, District Kangra (H. P.).

Hence this proclamation is hereby issued to the general
public to file their objection, if any, before this court on
or before 16-4-1990 at 10. A. M. personally or through an
authorised agent, failing which *ex parte* proceeding shall
be granted in favour of the applicant.

Given under my hand and the seal of this court today
the 7th day of March, 1990.

Seal.

BHAGWAN DASS MADAN,
Executive Magistrate,
Indora, District Kangra (H. P.).

In the Court of Shri Bhagwan Dass Madan, Executive
Magistrate, Indora, District Kangra (H.P.)

Shri Amar Singh son of Sankar Singh, resident of
village Indora, District Kangra, H. P. .. Applicant.

Versus

General public

.. Respondent.

Application under section 13(3) of the Births and Deaths Registration Act, 1969.

To

The general public.

Whereas the above noted applicant have moved an application duly supported with an affidavit under section 13(3) of Births and Deaths Registration Act, 1969 for registration of his grandson named Gopal Singh son of Shri Subhas Singh who was born on 2-2-1987 in village Indora, Tehsil Indora, District Kangra H. P.

Hence this proclamation is hereby issued to the general public to file their objection, if any, before this court on or before 16-4-1990 at 10-00 A. M. either personally or through authorised agent, failing which ex parte shall be granted in favour of the applicant.

Given under my hand and the seal of this court today the 7th March, 1990.

Seal.

BHAGWAN DASS MADAN,
Executive Magistrate,
Indora, District Kangra.

ब आदेश श्री मस्त राम शर्मा तहसीलदार/सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, कांगड़ा

मुकदमा नं० 454/88

1. राजेश कुमार, 2. राकेश कुमार, माईनर पुत्रान प्रकाश पुत्र शांतीग्राम, निवासी मुहान कटवाल लाहड़, मोजा दोनतपुर, तहसील व जिला कांगड़ा

वनाम

1. सूकू पुत्र सुरजन पुत्र घौना, 2. श्रीमती शान्ती पुत्री सुरजन पुत्र घौना, 3. सुरिन्दर कुमार पुत्र गुलाबा, प्रवीण पुत्री गुलाबा, श्रीमती कृष्णा देवी विधवा गुलाबा, राजमल पुत्र दमोदरी देवा गुलाबा, कुमारी कमना पुत्री दमोदरी, निवासी मुहान कटवाल लाहड़, मोजा दोनतपुर तहसील व जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

प्रार्थना-पत्र नकसीम अराजी खाता नं० 22, खतीनी नं० 51 ता० 53, रकबा तादादी 6-79-88 हैक्टयर बाक्या महाल, कटवाल लाहड़, मोजा दोनतपुर।

नोटिस:

उपरोक्त प्रतिवादीगण को कई बार समन द्वारा इत्तलाह दी गई कि वह हाजर अदालत आवें मगर समन की तामील साधारण तरीका से न हो सकी। अतः वजहिया इस्तहार उक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 24-4-90 प्रातः 10 बजे हमारी अदालत तहसील कांगड़ा में असालतन या बकालतन हाजर आकर मुकदमा को पेरवी करें। अन्यथा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह इस्तहार हमारी अदालत में आज हस्ताक्षर व मोहर से दिनांक 8-3-1990 को जारी हुआ।

मोहर।

मस्त राम शर्मा,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
कांगड़ा।

ब अदालत श्री सीता राम शर्मा, तहसीलदार/सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी कांगड़ा

मुकदमा नं० .../89

श्री केदार नाथ पुत्र नारायण दाम, वासी नगरोटा बगवां

वनाम

श्री पूनू राम, मनी राम, राम लाल पुत्र जानकी राम, वासी

सतरेहड़, मोजा नगरोटा बगवां।

दरखास्त भूमि खाता नं० 31 मिन. खतीनी नं० 63 मिन. खसरा नं० 82-82, किता 2, तादादी 0-0 6-72 हैक्टयर बाक्या महाल सतरेहड़, मोजा नगरोटा बगवां।

नोटिस:

मुकदमा उनवानवाला में उपरोक्त प्रतिवादी गण को कई बार समन द्वारा इत्तलाह दी गई कि वह बगवां पेरवी मुकदमा हाजर अदालत आवें, मगर समन की तामील साधारण तरीका से न हो सकी और प्रत्यार्थीगण जानबूझ कर समन की तामील नहीं कर रहे हैं। अतः वजहिया इस्तहार उपरोक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 19-4-90 प्रातः 10 बजे हमारी अदालत तहसील कांगड़ा में असालतन या बकालतन हाजर आकर मुकदमा को पेरवी करें अन्यथा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 8-3-1990 को जारी हुआ।

सीता राम शर्मा,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा।

ब अदालत श्री जितेन्द्र सिंह नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील ददाह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

मिमल नं० 5/88

तारीख मरजुमा 16-5-88

नान्टा राम पुत्र श्री नानकू, निवासी कांगड़ा फैलग, उप-तहसील, ददाह, जिला सिरमौर (हि० प्र०)

फरीक अब्बल।

वनाम

श्री सुरतु पुत्र श्री शिरुनू, निवासी कांगड़ा फैलग, उप-तहसील ददाह, जिला सिरमौर (हि० प्र०)

फरीक दायम।

दरखास्त सेहतु इन्द्राज बावत अराजी मन्दरजा खाता/खतीनी नं० 1/4, खसरा नं० 243, 244, किता 2, तादादी 4-7 बीघे बाका मोजा कांगड़ा फैलग, उप-तहसील ददाह जिला सिरमौर (हि० प्र०)।

ब मुकदमा मुन्दर्जा उनवान वाला में फरीक दायम श्री सुरतु पर समन की तामील मृतबिक रिपोर्ट तामील कुनिदा साधारण तरीके से होनी न मुमकिन है और रिपोर्ट तामिल कुनिदा से यह भी जाहिर होता है कि सुरतु उपरोक्त मजकूर फौत हो चुका है और उसके जाईज वारसान को सही पता इलाका में किसी को मालूम नहीं है।

अतः वजहिया इस्तहार हुआ श्री सुरतु उपरोक्त मजकूर के कोई जायज वारीस हो तो वह असालतन या बकालतन इस अदालत में मुकरेरा तारीख मिति 16-4-1990 को हाजिर अदालत हो कर पेरवी मुकदमा करें। बसुरत दोगर मुकदमा हुआ की सुनवाई एकतरफा करके आगामी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक, 8 मार्च 1990 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

जितेन्द्र सिंह नेगी,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील ददाह, जिला सिरमौर।

अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, सोलन (हि० प्र०)

मुकदमा नं० 15/13-बी आफ 88/89

लिखि दायरा: 14-6-1989

उनवान मुकदमा दरखास्त दस्तु खमरा गिरदावरी व कागजात

माल खसरा नं० 5, 12, 38, 39, 60, 66, 72, 61, 9, 11, 37 व 75 कित्ता 12 तादादी 25 बीघा 7 बिस्वा बाका मौजा कठपार, परगना हरीपुर, तहसील व जिला सोलन :

विषय : तनदोक ई० नं० 317, गांव सलवाहण, तहसील सदर जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . . मकफूद उलखवरी ।

श्री चेत राम वनाम श्रीमती गिनी वनरा

मुकद्दमा उन्वान वाला उपरोक्त में 1. श्रीमती शिवी पुत्री श्री मोनाउ, 2. श्री देवी दास पुत्र श्री रिखी राम, 3. श्री माधु राम पुत्र श्री कर्म दास, 4. श्रीमती फूला देवी पुत्री श्री तुलसिया 5. श्री मन्जुवार मिह पुत्र श्री जटू सभी निवासीयान कठपार परगना हरीपुर, तहसील व जिला सोलन व 6. श्री राम मिह, 7. दिला राम, 8. श्रीमती रोजनी देवी, 9. श्रीमती बन्ता देवी सभी पुत्र व पुत्रियां श्री मंगलू, 10. श्रीमती संवारु विधवा श्री मंगलू सभी निवासीयान शमलेच, तहसील व जिला सोलन पर तामील बजरिया समन मोका हजा में नहीं हो रही है। अतः इस्तहार हजा के जरिये उपरोक्त ग्रामासीयान को सूचित किया जाता है कि वह तारीख 23-4-1990 अमालतन व वकालतन अदालत हजा में हाजिर आवें। अदम पैरवी मुकद्दमा कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी ।

आज दिनांक 1-3-1990 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया ।

मोहर ।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ष, सोलन ।

व अदालत श्री जे० पी० शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

वमुकद्दमा

जैवन्ती विधवा मोहिन्द्र, निवासी बाह, ई० भद्राता . . . प्रायिन ।

वनाम

सर्वश्री पंजकू पुत्र दया राम, बंसी लाल पुत्र कर्म सिंह, रूलदु पुत्र तुलसिया, अमर सिंह पुत्र किशन, शांति विधवा टोडर, निवासी बाह, ई० भद्राता . . . प्रतिपक्षीगण ।

दख्खास्त तकसीम अराजी ।

उपरोक्त मुकद्दमा में फरीक दोयम को कई बार इस न्यायालय से समन जारी हुये लेकिन उन पर तामील समन नहीं हो रही है अतः न्यायालय को विश्वास हो चुका है कि उन पर तामील समन साधारण तरीके से होनी कठिन है ।

अतः उपरोक्त फरीक दोयम को बजरिया इस्तहार सूचित किया जाता है कि व अमालतन या वकालतन दिनांक 21-4-1990 को समय 10 बजे प्रातः हमारे न्यायालय सरकाघाट में हाजर हो कर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा कार्यवाही जास्ता अमल में लाई जावेगी ।

हस्ताक्षर हमारे व मोहर अदालत से मिति 2-3-1990 को जारी हुआ ।

मोहर ।

जे० पी० शर्मा,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सरकाघाट, जिला मण्डी ।

व अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, भू०-एकीकरण विभाग, सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

ईत्तकाल नं० नाम गांव/मौजा किस्म ई० तारीख पेशी
317 सलवाहण मकफूद उलखवरी 4-4-1990

हुरू पुत्र शिवू वनाम कर्मू, चूजूर, ब्रेस्ती, जानकी, द्रोपती, पंजकी, प्रमदयाल, कृष्ण चन्द, चतराम, माधू पिसरान आलमू, मोती, निवासी सलवाहण, तहसील सदर, जिला मण्डी ।

उक्त विषय के सन्दर्भ में ईत्तकाल नं० 317, मुहल सलवाहण, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश अवाहस्ताक्षरी के न्यायालय में जर समायत है । हुरू पुत्र शिवू, बार-बार इतलाह के वाकबूद हाजर नहीं आ रहा है प्रतिवादी का कथन है कि वह ग्रसा 30-35 वर्ष से लापता है उसक जीवित व मरने की कोई खबर न है । इसलिए उक्त ईत्तकाल के निर्णय हेतु ग्राम सूचित किया जाता है कि हुरू की वरास्त मकफूद उलखवरी वनाम कर्मू, चूजूर, ब्रेस्ती पिसरान मोती व जानकी, द्रामती, पंजकी, प्रमदयाल, कृष्ण चन्द, चेत राम, माधू, पिसरान आलमू तनदोक करने में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 4-4-1990 को वराए पैरवी अमालतन या वकालतन सुबह 10 बजे मेरी अदालत मुकाम सुन्दरनगर हाजर आ सकना है । अन्यथा ई० नं० 317 गांव सलवाहण वनाम वादीगण तनदोक कर दिया जाएगा । इसके पश्चात् कोई एतराज काबले समायत नहीं होगा ।

यह इस्तहार आज दिनांक 7-3-1990 को मोहर अदालत व हस्ताक्षर महित जारी हुआ ।

मोहर ।

एम० एल० कटारिया,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भू०-एकीकरण विभाग, सुन्दरनगर, (हि० प्र०) ।

व अदालत श्री अर्जुन सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं भू-सुधार अधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि० प्र०)

मिसल नं० 10/T/89 दख्खी इन्द्राज मौजा वमाल, तहसील ऊना ।

देस राज पुत्र बालक राम, जात बाहती, गांव वमाल, तहसील ऊना ।

वनाम

1. देस राज, 2. रमेश चन्द, 3. सन्तोष चन्द, 4. व्यासा देवी पुर्वा, 5. जानकी देवी पुत्री सुन्दर, जात बाहती, गांव वमाल, तहसील ऊना ।

दख्खास्त वाकत दख्खी इन्द्राज बतौर गर-मौरसी, खेवट नं० 497, खतीनी नं० 738, खसरा नं० 821, तादादी भूमि 1-4 सरला मुताविक जमाबन्दी साल 1981-82, वाक्या मौजा वमाल ।

नोटिस वनाम प्रतिवादीगण 1. देस राज, 2. रमेश चन्द, 3. सन्तोष चन्द पुत्र जानकी देवी, 4. परमिन्द्र, 5. अनोता पुत्रीया व्यासा देवी, मौजा कोईडी, तहसील अम्ब, जिला ऊना ।

उपरोक्त मुकद्दमा दख्खी इन्द्राज इस अदालत में जरै समायत है उपरोक्त प्रतिवादीगण देस राज, रमेश चन्द, सन्तोष चन्द पुत्र जानकी देवी, परमिन्द्र, अनोता पुत्री व्यासा, मौजा कोईडी को भमन जारी हुए थे । इनकी तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है क्योंकि Regd. A D. भी बिना तामील वापम प्राप्त हुई है इस लिए प्रतिवादीगण को जर आर्डर 5, रूल 20, सी० पी० सी० के अधीन नोटिस जारी किया जा कर सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 19-4-1990 को अदालत हजा में अमालतन या वकालतन हाजर होकर मुकद्दमा की पैरवी करें । अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाकर मुकद्दमा का फैसला कर दिया जाएगा ।

आज दिनांक 19-3-1990 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ ।

मोहर ।

अर्जुन सिंह ठाकुर,
तहसीलदार एवं भू-सुधार अधिकारी,
ऊना, हि० प्र० ।

HIMACHAL PRADESH UNIVERSITY, SHIMLA-5
"CONDUCT BRANCH"

NOTIFICATIONS

Shimla-5, the 14th March, 1990.

No. 6-26/88-HPU (Conduct).—Shri Tulsi Ram Sharma

son of Shri Mathu Ram (Registration No. 71-OS-17) has been allowed to change his name from 'Tulsi Ram Sharma' to 'Tulsi Raman'. In future his name in the University record will be shown as 'Tulsi Raman' alias 'Tulsi Ram Sharma'.

Dharni son of Shri Balak Ram, registration No. 84-PMA-844 has been allowed to change his name from 'Salig Ram Dharni' to 'Rajinder Kumar Dharni'. In future his name in the University record will be shown as 'Rajinder Kumar Dharni' alias 'Salig Ram Dharni'.

Shimla-5, the 14th March, 1990

No. 6-26/88-HPU (Conduct).—Shri Salig Ram

Sd/-
Assistant Registrar (Conduct),
H. P. University, Shimla-5.

भाग 6—भारतीय राजपत्र इत्यादि में से पुनः प्रकाशन

अन्य

भाग 7—भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की वैधानिक अधिसूचनाएं तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी अधिसूचनाएं ।

अन्य

अनुपूरक

अन्य

भाग I

लोक निर्माण विभाग

विवरण

अधिसूचना

जिला : मण्डी

तहसील : युनाग

शिमला-2, 14 मार्च, 1990

संख्या लो 0 नि 0 (ख) 7(1) 161/89.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव लाहड़ी, बरयोमी और नेहरा, तहसील युनाग, जिला मण्डी में केलोधार-छतरी सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करने अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिसर में जैसा कि निम्न विवरणों में निदिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, को जानकारी के लिए भूमि-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा श्रद्धा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों, उनके कर्मचारियों और अधिकारियों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सह्य प्राधिकार देते हैं ।

4. कोई भी हितवद्ध व्यक्ति, जिसे उक्त परिसर में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तिस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भ-अर्जन समिति, लोक निर्माण विभाग, मण्डी के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है ।

गांव 1	खसरा नं० 2	क्षेत्र वर्ग वि० बिस्वा० 3 4 5		
लाहड़ी/389	114/2/1	0	8	18
	115/2/1	0	3	19
किता . . . 2		0	12	17
बरयोमी/314	276/3/1	0	11	4
किता . . . 1		0	11	4
नेहरा/385	260/1	0	5	18
	213	0	2	17
	196/1	0	5	3
	109/1	0	9	10
	155/1	0	4	2
	214/1	0	0	14
किता . . . 6		1	8	4

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
आयुक्त एवं सचिव ।